



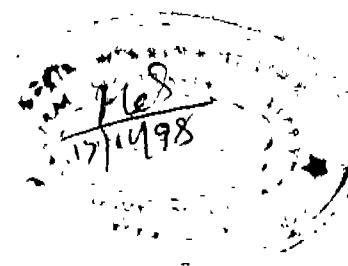
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 137]
No. 137]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 1998/आषाढ़ 3, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 1998/ASADHA 3, 1920

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 जून, 1998

सं. 7(1)/98-डी.पी.ई.ए.—रसायन और उर्वरक मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने 1981 से 1987 के बीच [जब तक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 लागू रहा] प्रपुंज औषधीं और सूत्रयोगों के विक्रय हेतु औषध कंपनियों द्वारा वसूल किए गए मूल्य से उत्पन्न देयताओं से संबंधित समस्त मामले की समीक्षा करने के लिए संकल्प सं. 23(2)/93-पी.आई-I दिनांक 21 मार्च, 1994 के तहत एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है। उक्त समिति का कार्यकाल संकल्प सं. 7(1)/96-डी.पी.ई.ए दिनांक 27 जून, 1997 के तहत 20 जून, 1998 तक बढ़ाया गया था। कार्य के हित में उक्त समिति का कार्यकाल 20 जून, 1998 से आगे और एक वर्ष, अर्थात् 20 जून 1999 तक की अवधि तक बढ़ाया जाता है।

2. समिति को अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए तथा बढ़ाए गए कार्यकाल के अन्दर अपनी सिफारिशों सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए।

एस. के. सूद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd June, 1998

No. 7(1)/98-DPEA.—The Deptt. of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers have constituted a Three Member Committee to review the entire matter relating to liabilities arising out of prices charged by the drug companies for the sale of bulk drug and formulations between 1981 to 1987 [till the Drugs (Prices Control) Order, 1979 remained in force], vide Resolution No. 23(2)/93-PI. I dated the 21st March, 1994. The tenure of the said Committee was extended upto 20th June, 1998, vide resolution No. 7(1)/96-DPEA dated the 27th June, 1997. In the interest of work, the tenure of the said Committee is extended for a further period of one year beyond 20th June, 1998 i.e. upto 20th June, 1999.

2. The Committee should complete its task and submit its recommendations to the Government within the extended tenure.

